Research Paper

E-ISSN NO : 2455-295X | IMPACT FACTOR VALUE : 5.983
VOLUME : 11 | ISSUE : 1 | SPECIAL ISSUE JANUARY-2025

भारत-चीन सीमा विवाद और तिब्बत की स्थिति का सामरिक मूल्यांकन

डॉ. सुमेश कुमार

सहायक प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन विभाग, राजकीय महाविद्यालय, अटेली (हरियाणा).

ABSTRACT:

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महाभारत और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में तिब्बत का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके साथ भारत का संपर्क वस्तुतः बौध्द धर्म के माध्यम से ही हुआ | भारत- तिब्बत सम्बन्ध का उल्लेख बौध्द साहित्य से मिलता है जिसमे भारत के विश्वविद्यालयो और उनके विद्वानों का अहम योगदान रहा |

चीन और तिब्बत ऐतिहासिक रूप से संघर्ष में लगे हुए हैं। तिब्बत पर नियंत्रण करना चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के शीर्ष लक्ष्यों में से एक था। तिब्बत चीन के लिए रणनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। चीन अच्छी तरह जानता था कि यदि तिब्बत पर शासन नहीं किया गया तो वह अंततः भारत के करीब आ जाएगा, जिसके साथ उसकी सीमा लगती है, मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और अतीत में दोनों देशों के बीच कोई शत्रुता नहीं रही है। वास्तव में, भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का बहुत सक्रिय दोतरफा आदान-प्रदान होता रहा है। चीन और भारत के बीच जटिल संबंधों में तिब्बत हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। तिब्बत को इसके महत्व के बावजूद अभी भी चीन-भारत संबंधों में एक उपेक्षित के रूप में देखा जाता है, जो द्विपक्षीय संबंधों पर एक काली छाया डालता है। अब समय आ गया है कि भारत को भी चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रुख अपनाना चाहिये।

KEYWORDS:

सीमा विवाद, सामरिक, भारत-तिब्बत सम्बन्ध, भारत-चीन संबंध, बौध्द साहित्य, द्विपक्षीय संबंध ।

परिचय

भारत- तिब्बत सम्बन्ध बहुत प्राचीन है इसे हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते है | महाभारत और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में तिब्बत का उल्लेख त्रिविष्टप नाम से मिलता है, लेकिन इसके साथ भारत का संपर्क वस्तुतः बौध्द धर्म के माध्यम से ही हुआ | भारत प्राचीन काल से अपनी संस्कृति, धर्म, शाशन संचालन प्रक्रिया और शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुका था | प्राचीन भारत में नालंदा और विक्रमशिला दो विश्व प्रसिध्द विश्वविद्यालय थे जहाँ विश्व के विभिन्न भागो से विद्वान और छात्र आते थे | तिब्बती विद्वान तारानाथ ने इसका विस्तृत वर्णन किया है | यहाँ के शिक्षक और विद्वान तिब्बत में इतने प्रसिध्द थे की कहा जाता है एक बार तिब्बत के राजा ने इस विश्वविद्यालय के प्रधान की तिब्बत में आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे थे ताकि स्वदेशी ज्ञान और जन- सामान्य की संस्कृति में रूचि जगाई जा सके | बिहार में एक अन्य प्रसिध्द विश्वविद्यालय था- ओदंतपुरी | पालवंश के राजाओं के संरक्षण में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी | इस विश्वविद्यालय से बहुत सरे बौध्द भिक्षु तिब्बत में जाकर बस गये थे |

शुरुआत में भारत- तिब्बत सम्बन्ध का उल्लेख बौध्द साहित्य से मिलता है जिसमे भारत के विश्वविद्यालयो और उनके विद्वानों का अहम योगदान रहा | नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कमलशील को तिब्बत के राजा ने निमंत्रित किया था | उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर पर विशेष लेप लगाकर उसे ल्हासा के विहार में सुरक्षित रखा गया था | ज्ञानभद्र, एक अन्य प्रकांड विद्वान थे जो अपने दोनों बेटों के साथ धर्म प्रचार के लिए तिब्बत गये | बिहार के ओदन्तपुरी विश्वविद्यालय के समान तिब्बत में एक नये बौध्द विहार की स्थापना की गई है | आचार्य अतीश विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे जिन्हें दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से भी जाना जाता था | वे ग्यारहवीं शताब्दी में तिब्बत गये और वहां बौध्द धर्म की सशक्त नींव डाली | थोनामी संभोता एक तिब्बती मंत्री था जो चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था | यहाँ से अध्ययन के बाद वह तिब्बत लौटा और वहां उसने बौध्द धर्म का प्रचार- प्रसार किया | तिब्बतियों की बड़ी संख्या ने बौध्द धर्म को स्वीकार किया यहाँ तक कि तिब्बत का राजा भी बौध्द बन गया था | उसने बौध्द धर्म को राजधर्म घोषित किया था | तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार तिब्बती राजा, सोंगत्सेन गम्पो और ठिसोंग-देत्सेन के प्रयासों से हुआ तथा उनके नाम तिब्बती इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गए हैं।

जब भारत ब्रिटेन के अधीन था उस समय ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने की ओर अग्रसर हुई | जुलाई 1904 में एक युवा ब्रिटिश कर्नल फ्रांसिस युनुगसबैंड ने ल्हासा के पवित्र शहर में प्रवेश किया और तिब्बतियों पर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपना पहला समझौता किया | क्राउन प्रतिनिधि के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करके, तिब्बत को लन्दन द्वारा एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया था| मार्च 1914 में, चीन के प्रति निष्पक्षता दिखाए के लिए लन्दन ने इस मुद्दे को निपटाने के लिए शिमला में एक त्रिपक्षीय सम्मलेन का आह्वान किया; इस सम्मलेन में पहली तीन मुख्य नायक वार्ता के लिए एक साथ एक मंच पर आये | इस मीटिंग का परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था क्योकि चीनियों ने केवल मुख्य दस्तावेज़ को प्रारंभ किया और इसकी पुष्टि नहीं की | ब्रिटिश और तिब्बती हालांकि एक आम सीमा पर सहमत हुए जिसे उन्होंने मानचित्र पर सीमांकित किया जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है | यह संधि तब भी लागु थी जब भारत अगस्त १९४७ में स्वतंत्र हुआ था | स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का तिब्बती सरकार के विदेश कार्यालय से शिमला कन्वेंशन की पुष्टि करने का अनुरोध किया | भारत सरकार के इस औपचारिक अनुरोध को तिब्बत के विदेश कार्यालय स्वीकार कर लिया जो तिब्बत की स्वतंत्र स्थिति का सबसे अच्छा प्रमाण है |

तिब्बत-भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चीन और तिब्बत ऐतिहासिक रूप से संघर्ष में लगे हुए हैं। तिब्बत पर नियंत्रण करना चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के शीर्ष लक्ष्यों में से एक था। तिब्बत चीन के लिए रणनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यह ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश भारत और चीन के बीच एक बफर ज़ोन के रूप में कार्य करता था। तिब्बत चीन का असुरक्षित पिछला दरवाज़ा है, जिसे कभी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में, जब चीन संघर्ष कर रहा था और मांचू राजवंश बिखर रहा था, तब अंग्रेजों ने तिब्बत में खुद को स्थापित कर लिया। चीन का मानना था कि नेहरू का स्वतंत्र भारत तिब्बत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति को आगे बढ़ा रहा था।

उस समय, तिब्बत ज्यादातर स्वतंत्र, अलग-थलग प्रांत था, लेकिन ब्रिटिश शासित भारत और चीन के किंग राजवंश के बीच स्थित होने के कारण यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। 1903-1904 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा एक सैन्य और कूटनीतिक मिशन जिसे यंगहसबैंड अभियान या यंगहसबैंड मिशन के रूप में जाना जाता है, ने तिब्बत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की। [6] ब्रिटिश सैन्य कमांडर और खोजकर्ता कर्नल फ्रांसिस यंगहसबैंड मिशन के प्रभारी थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा तिब्बत के साथ व्यापार और सीमा समझौतों पर बातचीत करने और यदि आवश्यक हो, तो अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए बल का सहारा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। दिसंबर 1903 में, अभियान तिब्बत में प्रवेश किया और तिब्बती सैनिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। अगस्त-सितंबर 1904

में हस्ताक्षरित इस समझौते ने तिब्बत पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया, जिससे तिब्बत को अपनी विदेश नीति को यूनाइटेड किंगडम के साथ समन्वयित करने की बाध्यता मिली। तिब्बत ने ब्रिटेन को एक बड़ी क्षतिपूर्ति देने के लिए भी सहमति व्यक्त की। यंगहसबैंड अभियान तिब्बत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसने तिब्बत को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया था। इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसे तिब्बत पर चीनी नियंत्रण के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया था, इसने क्षेत्र में भू-राजनीतिक संतुलन के लिए नतीजे निकाले।

चीन अच्छी तरह जानता था कि यदि तिब्बत पर शासन नहीं किया गया तो वह अंततः भारत के करीब आ जाएगा, जिसके साथ उसकी सीमा लगती है, मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और अतीत में दोनों देशों के बीच कोई शत्रुता नहीं रही है। वास्तव में, भारत और तिब्बत के बीच लंबे समय से धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का बहुत सक्रिय दोतरफा आदान-प्रदान होता रहा है। भारत, वह देश जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, तिब्बती इसे अपना आध्यात्मिक गुरु और आर्यभूमि, या "पवित्र भूमि" दोनों के रूप में देखते हैं। [8] जिस तरह से तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को हिंदू मिथक और परंपरा में भगवान शिव के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है, उसी तरह उन्हें उन धर्मों में सबसे पवित्र शिखर और झील भी माना जाता है। भारत के ऊपरी हिमालय पर्वतों में, महायान बौद्ध धर्म का तिब्बती स्कूल प्रमुख विचारधारा है 1959 में वर्तमान दलाई लामा के भारत भागने से पचास साल पहले, उनके पूर्ववर्ती, तेरहवें दलाई लामा, 1910 में चीनी सेना के ल्हासा पहुंचने पर सुरक्षा के लिए ब्रिटिश भारत भाग गए थे।

अतीत में, तिब्बत एक प्राचीन सभ्यता के संरक्षण के रूप में फला-फूला, बाहरी दुनिया के शोरगुल और उथल-पुथल से दूर, एक विशाल आकाश के एकांत और शांत वातावरण में रहा। अपनी संपत्ति या शस्त्रागार के लिए नहीं, तिब्बत अपनी आध्यात्मिक महिमा की ऊंचाइयों और अपने बौद्धिक दर्शन की व्यापकता के लिए प्रसिद्ध था। इस सभ्यता का केंद्रीय विषय धर्म रहा है। तिब्बत के पर्वतीय दुर्गों, घाटियों और पठारों में, जीवन अपनी आध्यात्मिक खोज में हाल ही तक कायम रहा, जब परिस्थितियों के बल ने चीजों के तरीके को बदल दिया। चीन और भारत के बीच जटिल संबंधों में तिब्बत हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। तिब्बत को इसके महत्व के बावजूद अभी भी चीन-भारत संबंधों में एक उपेक्षित के रूप में देखा जाता है, जो द्विपक्षीय संबंधों पर एक काली छाया डालता है। भारत ने तिब्बत के प्रति अत्यधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है और तिब्बत को एक चीनी स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है।

भारत-चीन सीमा विवाद में तिब्बत की स्थिति

चीन के साथ भारत की सीमा पर संघर्ष दो बड़े क्षेत्रों, अर्थात् लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रित है। चीन का कहना है कि उत्तरार्द्ध "दक्षिणी तिब्बत" का हिस्सा है और पूर्व अक्साई चिन क्षेत्र का हिस्सा है जो इसके प्रशासन के अधीन है। तिब्बत पर चीन के कब्जे का इतिहास इन दोनों संघर्षों का मूल कारण है। इन संघर्षों की सबसे हालिया अभिव्यक्ति जून 2020 में भारतीय गैलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें थीं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में मौतें हुईं। ऐसी जानकारी है कि अगस्त 2020 में, एक तिब्बती जो एसएफएफ (विशेष सीमा बल) का हिस्सा है, ने क्षेत्र में अपने एक गश्त के दौरान एक भूमि खदान विस्फोट में अपनी जान गंवा दी। चीन-भारतीय सीमा के पास अगस्त की इस घटना में तिब्बती योद्धा न्यिमा तेनज़िन की जान चली गई ऐसी घटनाएँ दर्शाती हैं कि तिब्बत भारत-चीन संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है और आगे भी रहेगा तथा उनके सीमा विवाद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा। परिणामस्वरूप, यह महत्वपूर्ण है कि आगे बढ़ते हुए, भारत चीन के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों पर एक मजबूत और स्पष्ट विदेश नीति विकसित करे और उसे लागू करे, जिसमें तिब्बत समस्या को गौण विचार के बजाय बातचीत में सबसे आगे रखा जाए।

भारत-चीन सीमा विवाद और तिब्बत

हज़ारों सालों तक तिब्बत ने चीन और भारत को अलग-थलग रखने और शांति बनाए रखने के लिए एक भौतिक अवरोध के रूप में काम किया। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर हमला करने और उस पर नियंत्रण करने के बाद से, भारत और चीन ने हाल ही में एक सीमा साझा करना शुरू किया है, और इसके साथ ही सीमा सुरक्षा के अंतर्निहित मुद्दे, जैसे कि सीमा का सीमांकन और सीमांकन और लोगों की आवाजाही और उस पार व्यापार का प्रवाह।

नए सीमा कानून में सात अध्याय और 62 अनुच्छेद हैं। चीन की सभी भूमि सीमाओं पर सीमा को सही ढंग से इंगित करने के लिए कानून द्वारा सीमा चिह्न लगाए जाने चाहिए। वैसे, भारत नए सीमा कानूनों से प्रभावित होने वाला एकमात्र देश नहीं है। भारत चीन के 14 अंतरराष्ट्रीय पड़ोसियों में से एक है, जिसकी 22,457 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा मंगोलिया और रूस के बाद तीसरे स्थान पर है। कानून यह भी अनिवार्य करता है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने, सीमा क्षेत्रों को खोलने और लोगों के जीवन और रोजगार को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए कार्रवाई करे। यह सीमा रक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास के समन्वय का भी आह्वान करता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए सीमा प्रतिबंधों का भारत पर प्रभाव पड़ेगा। ये दिशा-निर्देश तब लागू होंगे जब भारत पीआरसी के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाश रहा है। इस कानून के साथ पहला मुद्दा यह है कि यह चीन की सहमति के बिना सीमा के पास किसी भी दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रोक लगाता है। हाल के वर्षों में चीन और भारत दोनों में निर्माण गतिविधि बढ़ी है, दोनों राष्ट्र तेज गति से सड़कें, पुल और सैन्य आवास बना रहे हैं। उत्तराखंड में बाराहोती मैदान, अरुणाचल प्रदेश का पूरा राज्य और 1959 क्लेम लाइन तक लद्दाख के हिस्से भी चीन के नए नक्शे में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नया कानून निर्दिष्ट करता है कि चीन का अपने आंतरिक जलमार्गों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, चाहे उसकी पड़ोसी सरकारों के हितों की परवाह न हो।

तिब्बत के बदलते परिवेश में चीन की भूमिका

चूँकि भारत की अधिकांश सीमाएँ और 3500 किलोमीटर का लद्दाख स्वायत्त क्षेत्र (LAC) तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के भीतर है, न कि शेष चीन में, तिब्बत को लंबे समय से भारत का सच्चा पड़ोसी माना जाता है। तिब्बती प्रतिनिधियों ने सीमाओं को परिभाषित करने के लिए चीनी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 1914 में ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद समझौते और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया, जिसने दोनों देशों को अलग कर दिया। इसके अतिरिक्त, भारत और चीन 1954 के समझौते में तिब्बत को "चीन के तिब्बत क्षेत्र" के रूप में मान्यता देने पर सहमत हुए। तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा और उनके कई समर्थक तिब्बती विद्रोह के बाद 1959 में भारत भाग गए। उन्हें और अन्य तिब्बती निर्वासितों को दिवंगत प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शरण दी आधिकारिक भारतीय नीति के अनुसार, दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं और भारत में रह रहे एक लाख से अधिक तिब्बती निर्वासितों को किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

चीन ने 1950 में तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, जब उसने तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसा करने के लिए, तिब्बत के साथ अधिक स्थिर पारगमन संबंध बनाना आवश्यक था। तिब्बत को चीन के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाले राजमार्ग 1954 तक पूरे हो गए थे। इसके अलावा, चीनियों का मानना था कि शुष्क और निर्जन अक्साई चिन क्षेत्र झिंजियांग से तिब्बत तक अपेक्षाकृत सीधा मार्ग प्रदान करता है। चीनी प्रशासन ने भारत को संतुष्ट करने के लिए सीमा मुद्दे पर विलंबकारी रणनीति का इस्तेमाल किया क्योंकि अक्साई चिन पर भारत का नियंत्रण था और उस पर भारत का दावा था। इसने एक साथ जमीन पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाए और एक मार्ग बनाने की योजना बनाई जो झिंजियांग को अक्साई चिन के माध्यम से तिब्बत से जोड़ेगा।

मई 1951 में चीन ने हम पर सत्रह सूत्री समझौता थोपा। भारत सरकार ने लद्दाख और उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी (नेफा) के सुदूर और कम आबादी वाले हिमालयी क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए, जिसे आमतौर पर तवांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश नेफा का नया नाम है। दलाई लामा को वश में करने और तिब्बत के साथ संपर्क सुधारने के लिए सड़क निर्माण परियोजनाओं को शुरू करने के बाद, चीन ने भारत और नेपाल के साथ तिब्बत के पारंपरिक आर्थिक संबंधों को कमजोर करने, तिब्बत में भारत के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारों को खत्म करने और तिब्बत पर चीन के कब्जे के लिए भारत की वैधता को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

सितंबर 1957 में तिब्बत और झिंजियांग को जोड़ने वाले अक्साई चिन मार्ग का निर्माण पूरा हो गया था। भारत स्वाभाविक रूप से सतर्क और चिंतित था, लेकिन उसने अगले साल तक अपना असंतोष व्यक्त नहीं किया। लेकिन चीन का रवैया और भी अधिक विरोधी हो गया। झोउ एनलाई के माध्यम से, दलाई लामा ने जनवरी 1958 में नेहरू को तिब्बत की यात्रा

करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन चीनियों ने यात्रा को स्थगित करना शुरू कर दिया। मुद्रित मानचित्रों पर चीन ने नेफा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दावा किया था, और चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र का उल्लंघन करने के अधिक मामले सामने आए थे। यह स्पष्ट है कि चीन-भारत संबंध खराब हो गए हैं।

यह स्पष्ट था कि चीन ने अक्साई चिन के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था, जिस पर भारत भी दावा करता था या नियंत्रण करता था, जो तिब्बत पर अपना अधिकार मजबूत करने के लिए की गई उसकी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप था। स्वाभाविक रूप से, इसने भारत को नाराज़ कर दिया। दूसरी ओर, चीन ने भारत की अमेरिकी पहल में भागीदारी के साथ-साथ भारत में तिब्बती प्रतिरोध आंदोलन के लिए अपने स्वयं के समर्थन पर आपत्ति जताई। सामूहिकीकरण को लागू करने के सरकार के प्रयास के दौरान खाम और अमदो में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जिसके परिणामस्वरूप कई मठों को नष्ट कर दिया गया और भिक्षुओं को मार डाला गया। कई शरणार्थी भी भारत भाग गए क्योंकि उनमें से सैकड़ों मध्य तिब्बत में आ गए। तिब्बत में तेजी से बिगड़ती स्थिति के परिणामस्वरूप दलाई लामा मार्च 1959 में भारत भाग गए।

तिब्बत पर भारत का बदलता रुख

भारत के विभिन्न कदमों से पता चलता है कि तिब्बत पर उसका रुख बदल रहा है। निर्वासित तिब्बती सरकार के नेता को 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, जिसका कुछ श्रेय भारत सरकार द्वारा दलाई लामा सहित सार्वजनिक मंचों के प्रबंधन को भी जाता है। 6 जुलाई को परम पावन के 88वें जन्मदिन पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से जन्मदिन की शुभकामनाएँ भेजीं, जो 2014 में शुरू हुई प्रथा को जारी रखती है। इसके अतिरिक्त, भारत ने इस वर्ष बौद्ध धर्म पर पहला विश्वव्यापी सम्मेलन प्रायोजित किया, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधान मंत्री ने किया और इसमें उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, भारत ने तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को आधिकारिक रूप से समर्थन देकर गलवान घाटी में संघर्ष के बाद अपना रुख बदल दिया। हालाँकि, भारत को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को आधिकारिक रूप से स्वीकार करके अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। वर्तमान में भारत में बसने वाले तिब्बतियों को लेकर एक कार्यकारी नीति (कानून नहीं) है।भारत की वर्तमान तिब्बती नीति भारत में बसने वाले तिब्बतियों के कल्याण एवं विकास हेतु महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह तिब्बत के मुख्य मुद्दों का कानूनी समर्थन नहीं करती है। उदाहरण के लिये तिब्बत के विध्वंसकारकों द्वारा तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग। अत: अब समय आ गया है कि भारत को भी चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रुख अपनाना चाहिये।

इसके अलावा भारत में तिब्बत की एक युवा और अशांत आबादी निवास करती है, जो दलाई लामा के गुज़रने के बाद अपने नेतृत्व और कमान संरचना हेतु भारत से बाहर दिखती है। अत: भारत को ऐसी स्थिति से बचने की भी ज़रुरत है।

निष्कर्ष

वर्तमान में, अधिकांश तिब्बती मध्यम मार्ग रणनीति का समर्थन करते हैं क्योंकि वे इसे परम पावन दलाई लामा (HHDL) की सुविचारित पसंद के रूप में देखते हैं। तिब्बत का लक्ष्य तिब्बती संस्कृति, क्षेत्र और राष्ट्रीय पहचान का संरक्षण और संरक्षण है, न कि चीन से सच्ची स्वतंत्रता। बदले में, चीनी लोगों के लिए सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी होगी। दुनिया ने इस रणनीति का समर्थन किया है। चीन और भारत की सरकारें अक्सर भारत-चीन सीमा संघर्ष के संदर्भ में तिब्बत तत्व को कम महत्व देती हैं क्योंकि वे एक शांतिपूर्ण और उत्पादक संबंध बनाना चाहते हैं। तिब्बती भारत सरकार के उनके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करने और उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं।

REFERENCES

1. फाइनेंशियल एक्सप्रेस। (2020)। भारत-तिब्बत संबंधों की किंवदंतियाँ: भारत-चीन गतिरोध के बीच, प्राचीन ट्रांस-हिमालयी बंधन पर एक नज़र। वित्तीय एक्सप्रेस।

2. लाडॉन, टी. (2023)। चीन के प्रति भारत के दृष्टिकोण में तिब्बत का पुनरुद्धार। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन.

3. पिल्लालमर्री, ए. (2020)। तिब्बत-लद्दाख संबंधों का इतिहास और उनके आधुनिक प्रभाव। राजनयिक.

4. सीकरी, आर. (2011)। भारत-चीन संबंधों में तिब्बत कारकo

5. स्ज़ेपैंस्की, के. (2019)। 1959 का तिब्बती विद्रोह। थॉट्को। https://www.thinkco.com/the-tibetan-uprising-of-1959-195267

6. तिब्बत नीति संस्थान। (2020)। तिब्बत नीति जर्नल. धर्मशाला: तिब्बत नीति संस्थान।

7. सेंट्रल अर्कांसस विश्वविद्यालय। (2023)। चीन/तिब्बत (1950-वर्तमान)। कॉनवे: सेंट्रल अर्कांसस विश्वविद्यालय। https://uca.edu/राजनीतिक विज्ञान/होम रिसर्चप्रोजेक्ट्स/डैडएम-प्रोजेक्ट/एशियापैसिफिक-क्षेत्र/चिनाटिबेट-1950-वर्तमान/ से लिया गया

8. ज़मल्हा, टी.जी. (2019)। 17-सूत्रीय समझौता-चीन ने क्या वादा किया, वास्तव में क्या पूरा किया और भविष्य? तिबर नीति संस्थान। https://tibetpolicy.net